जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 236 प्रभात चूरू, मंगलवार 23 दिसम्बर, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

क्या बंगाल में भाजपा का ''ट्रंप कार्ड'' साबित होंगे नए अध्यक्ष नितिन नबीन

बंगाल में भाजपा ने ''भद्रलोक'' (जिसमें कायस्थ अधिक हैं) वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में एक ''ट्रम्प कार्ड'' के रूप में उभरेंगे, जहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं।

बिहार चुनावों के सबक पश्चिम बंगाल में भाजपा के काम नहीं आयेंगे। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन के खिलाफ 0.1 प्रतिशत वोट शेयर के अंतर के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2021 के पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का वोट शेयर 10 प्रतिशत अधिक था। बिहार में भाजपा की सफलता में छोटे दलों, जिनमें एलजेपी (आरवी) शामिल है, के साथ गठबंधन का बड़ा योगदान था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ

- बंगाल में हालांकि भद्रलोक के वोटर्स की संख्या कम है पर वे आम वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की कई नामचीन हस्तियां इसी वर्ग से आती हैं, जैसे, स्वामी विवेकानन्द, अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, ज्योति बसु, सत्यजित रे, बिमल मित्र आदि।
- बिहार में भाजपा के गठबंधन एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन में मात्र 0.1 प्रतिशत का वोट अंतर था पर बंगाल में तृणमूल का वोट शेयर भाजपा से 10 प्रतिशत अधिक है। बिहार के विपरीत यहां भाजपा को छोटे-छोटे दलों का सहारा भी नहीं है।
- सवाल यह है कि क्या भद्रलोक को साधकर भाजपा तृणमूल के आसपास पहुंच पाएगी?

केवल वामपंथी और कांग्रेस ही अन्य प्रमुख दल हैं, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के भी छोटी-मोटी संख्या में ही चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की महिला वोटरों पर काफी मजबूत पकड़ है। तो, भाजपा इन चुनौतियों से कैसे काबू पायेगी।

जाहिर है, भाजपा का सबसे अच्छा विकल्प, टीएमसी के साथ ही, वामपंथी और कांग्रेस के मूल समर्थन आधार को साधना है और उन 'भद्रलोक' वोटरों की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना है, जो संख्या में कम होते हुए भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वह जगह है, जहाँ नबीन, जो कि कायस्थ जाति से हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद है।

बंगाल के कायस्थ, जो शिक्षित और प्रभावशाली हैं, अपनी प्राचीन परंपरा पर गर्व करते हैं। जाने-माने बंगाली कायस्थों में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु, चितरंजन दास, सत्यजीत रे, बिमल मित्र, जैमिनी राय, अमर्त्य सेन और सर जदुनाथ सरकार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि नये कार्यकारी अध्यक्ष, अपने जमीनी दृष्टिकोण के साथ, इस वर्ग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारत हिंदू राष्ट्र है'

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 दिसंबर इस बात पर जोर देते हुए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि इसके लिए किसी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच है।

आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक रहेगा जब तक देश में भारतीय संस्कृति को महत्व दिया जाता रहेगा।

भागवत ने कोलकाता में आरएसएस के '100 व्याख्यान माला'

- संघ प्रमुख भागवत ने यह दावा करते हुए कहा, संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो भी ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है यह सत्य है।

कार्यक्रम में कहा, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। हमें नहीं पता यह कब से हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी हमें संविधान की मंजूरी चाहिए? हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, वह भारतीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीएमसी चुनाव में एक हुई मुम्बई की ''फर्स्ट फैमिली''

20 सालों में यह पहली बार है जब उद्धव और राज ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। मुंबई की राजनीति में 'पहला परिवार' माने जाने वाले ठाकरे परिवार ने सोमवार सुबह एक बड़े चुनावी पुनर्मिलन की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर इस परिवार में आखिरकार सहमति बन गई है।

पिछले 20 वर्षों में यह पहला अवसर होगा, जब ठाकरे परिवार के दो सबसे बड़े नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

इस बीच, कांग्रेस इस व्यवस्था का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थिति महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर तनाव को दर्शाती है, खासकर ठाकरे भाइयों के एकजुट होने के बाद। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में एमवीए को झटका लगने के बाद भी, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक वापसी की उम्मीद है।

बड़े संकटों के दौर में, दलितों, मुसलमानों और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों ने कांग्रेस के साथ खडे होकर, देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा जताया है।

- बीएमसी की 227 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 157 और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
- इस नई व्यवस्था में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सहयोगी दलों, कांग्रेस व एनसीपी (शरद पवार) को कोई जगह नहीं मिली है इससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित नहीं रहे और भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस ने भी इन चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक हल्की सी चुनौती पेश की।

इस सफलता का श्रेय कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रतिभा धनोरकर और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाले को जाता है।

कांग्रेस द्वारा जीते गये कुल 34 नगर परिषद अध्यक्ष पदों में से आठ सीटें चंद्रपुर जिले की और तीन सीटें बुलढ़ाणा जिले की थीं।

विश्वजीत कदम अपने गढ़ को बचाने में सफल रहे, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस विधायक अमित देशमुख अपनी पकड़ बनाए रखने में असफल रहे।

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में, भाजपा ने कुल 288 में से 120 नगर परिषद अध्यक्ष पद जीते, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 56 और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 36 पद मिले।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सूत्रों ने बताया कि शिव सेना बीएमसी की 227 सीटों में से 157 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष 70 सीटों पर उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने उम्मीदवार उतारेगी।

इस व्यवस्था के बाद, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना-नेतृत्व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग की सफलता के बीच गडकरी फिर विवादों में

उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है कि ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटों को व्यवसायिक लाभ पहुंचाया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत की 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण नीति (ई 20) को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद मुख्य रूप से हितों के टकराव के आरोपों, वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं और राजनीतिक विरोध पर केन्द्रित है।

उन पर लगाए गए प्रमुख आरोपों में सबसे अहम हितों के टकराव का है। सितंबर 2025 में कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी ने सरकारी नीति का इस्तेमाल अपने परिवार के व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए किया।

आरोपों के अनुसार, उनके बेटे निखिल गडकरी द्वारा संचालित सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की आय वित्त वर्ष 2024

- एक विवाद यह भी है कि ऐथनॉल युक्त पैट्रोल-डीज़ल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और वाहनों का माइलेज भी घट गया है।
- लेकिन नितिन गडकरी इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं, उनका कहना है कि पैट्रोल लॉबी पैसे देकर उनके खिलाफ यह दुष्प्रचार करवा रही है।

की पहली तिमाही में 17.47 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 510 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

इसी तरह, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी द्वारा संचालित मानस एग्रो इंडस्ट्रीज भी एथेनॉल सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की एक बड़ी कंपनी बताई जाती है। आलोचकों का कहना है कि ई20 ईंधन को पूरे देश में तेजी से लागू किए जाने के कारण इन कंपनियों को असाधारण मुनाफा हुआ।

वाहनों के प्रदर्शन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कई उपभोक्ताओं और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ई20 फ्यूल कोरोसिव (संक्षारक) प्रकृति का है और अप्रैल 2023 से पहले बने वाहनों के इंजनों की उम्र कम कर सकता है। कुछ रिपोर्टों में माइलेज में 3 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट और फ्यूल सिस्टम तथा रबर गैस्केट को नुकसान की आशंका जताई गई है।

नितिन गडकरी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें पेड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आईपीएस पंकज चौधरी के बकाया प्रमोशनों पर प्रोविज़नल तौर पर विचार करें'

जयपुर, 22 दिसंबर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह डीपीसी के तहत उनके बकाया चल रहे प्रमोशन पर प्रोविजनल तौर पर विचार

- केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) ने राज्य सरकार को निर्देश दिये।

करे। अधिकरण ने यह आदेश पंकज चौधरी के प्रार्थना पत्र पर दिए।

मामले से जुडे अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी के खिलाफ चल रहे केसों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के प्रमोशन शामिल हैं। इसके साथ ही साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन भी रुका हुआ है। राज्य सरकार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग में 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, भारत की बड़ी उपलब्धि

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि तय समय से 5 साल पहले ही प्राप्त कर ली गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भारत को ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में 20 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्ति तय अवधि से पांच साल पहले ही हो गई है, जिससे कच्चे तेल के आयात व्यय में कटौती हुई है और यह सतत ईंधन परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के फ्यूल पंपों पर दशकों की सबसे बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है। देश का ऐथनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम पायलट चरण से राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है, जिसमें ऐथनॉल सप्लाई इयर (ईएसवाय) 2024-25 में ब्लैंडिंग औसतन 19 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और ईएसवाय 2025-26 में ई 20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथनॉल का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।

पिछले पांच वर्षों में, ब्लैंडिंग 8.10 प्रतिशत से बढ़कर ईएसवाय 2020-21 में 14.60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जब 707.40 करोड़ लीटर ऐथनॉल पेट्रोल में मिलाया गया। बिल्कुल हाल ही में ईएसवाय (नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक) में, 1,022.4 करोड़ लीटर ऐथनॉल मिलाया गया, जिससे औसतन 19.24 प्रतिशत की ब्लैंडिंग हासिल हुई, जो ई 20 लक्ष्य के बेहद करीब है।

- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाश्म ईंधन (पैट्रोल-डीज़ल) से इकोफ्रैंडली ईंधन के इस्तेमाल की तरफ जाने की दिशा में यह बड़ी सफलता है।
- ऐथनॉल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर है पहले स्थान पर यूएसए तथा दूसरे पर ब्राज़ील है।

यह जानकारी 8 दिसम्बर 2025 को राज्य सभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई थी।

इंडियन शुगर एण्ड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) की वार्षिक आम बैठक के दौरान, दीपक बलानी, महासचिव, आईएसएमए ने कहा: ''भारत ने ई 20 के लक्ष्य को बहुत तेज़ी से हासिल किया है। लक्ष्य 2030 तक 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग का था, लेकिन हम इसे पांच साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। जो काम ब्राजील जैसे देशों ने 20 साल में किया, हमने वह सिर्फ 7-8 साल में कर दिखाया।

ऐथनॉल ब्लैंडिंग भारत को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की बचत में भी मदद कर रहा है, क्योंकि यह कच्चे तेल के आयात बिल को कम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 दिसम्बर 2025 को संसद में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ऐथनॉल ब्लैंडिंग की वजह से देश ने 1,55,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

इन लाभों के बावजूद, और 2024 में 6.2 बिलियन लीटर ऐथनॉल का उत्पादन करने के बावजूद, भारत अभी भी वैश्विक नेताओं, अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे है, जैसा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से पता चलता है।

वैश्विक ऐथनॉल उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत (61.4 बिलियन लीटर) है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वनरक्षक पेपर लीक में लेखाकार व वनरक्षक गिरफ्तार

जयपुर, 22 दिसंबर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने वनरक्षक भर्ती-2020 परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, पेपर पढ़ाने वाले लेखाकार सहित वनरक्षक को गिरफ्तार किया है। अब जाकर एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि उदयपुर व बांसवाड़ा के अलावा जयपुर में भी वनरक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ

- एसओजी ने अपने घर पर लीक पेपर पढ़वाने वाले वनरक्षक तथा लीक पेपर पढ़कर वनरक्षक की नौकरी हासिल करने वाले को गिरफ्तार किया।

था। जयपुर में एक लेखाकार ने अपने घर पर वनरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़वाया था। इसके बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लेखाकार सहित, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वाले वनरक्षक को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साले-बहनोई हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के पिछले दिनों गिरफ्तार मुख्य आरोपी जबराराम से पूछताछ में पता चला कि टोडाभीम निवासी लेखाकार अमन जोरवाल ने जयपुर में अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घोषणा के साथ ही झटका लगा भारत न्यूज़ीलैंड ट्रेड डील को

न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे ''बैड डील'' करार दिया

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 दिसंबर। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा बड़े जोर-शोर से घोषित मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट - एफटीए) को एक उस समय एक तगड़ा झटका लगा, जब सत्ताधारी गठबंधन के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे ''खराब समझौता'' करार देते हुए कहा कि यह ''बहुत अधिक देने'' तथा ''बहुत कम'' प्राप्त करने वाला समझौता है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते को स्वीकरण एक टेलीफोन कॉल के दौरान किया, जो द्विपक्षीय, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के एक बड़े विस्तार का संकेत देता है। इस समझौते पर तीन महीनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और 2026 में यह क्रियान्वित हो जायेगा।

दोनों पक्षों ने इसे ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी बताया, और यह भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए रिकॉर्ड नौ महीने में पूरा हो गया। इस समझौते की विधिवत बातचीत पीएम लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई थी।

न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री पीटर्स ने न्यू दिल्ली और वेलिंगटन के बीच हुए इस एफटीए का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व वाली सरकार ने डील में ''सब्स्टैंस'' का ध्यान नहीं रखा और शीघ्र डील होने पर ध्यान रखा।

पीटर्स, जो ''न्यूज़ीलैंड फर्स्ट पार्टी'' के नेता और सरकार में गठबंधन साझीदार हैं, ने कहा कि उनकी पार्टी ''खेद सहित'' इस समझौते के खिलाफ है और जब यह संसद में पेश होगा तो वे इसके सक्षम कानून का रूप लेने के खिलाफ मतदान करेंगे।

- विंस्टन पीटर्स ने कहा, इसमें न्यूज़ीलैंड को बहुत कुछ देना पड़ेगा पर बदले में उसे बहुत कम मिलेगा। पीटर्स न्यूज़ीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता हैं, जो न्यूज़ीलैंड की गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
- भारत और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने टेलिफोन वार्ता में इस डील की घोषणा की। इस डील पर तीन माह के भीतर हस्ताक्षर होने और इसके 2026 में क्रियान्वित होने की संभावना है।

पीटर्स ने एक्स पर लिखा, ''हम भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को न तो मुक्त मानते हैं और न ही निष्पक्ष।'' उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूज़ीलैंड के आर्थिक और श्रमिक हितों की रक्षा करने में विफल रहा है।

उन्होंने कहा, दुख की बात यह है कि यह न्यूज़ीलैंड के लिए एक खराब समझौता है। यह देता बहुत ज्यादा है, खासकर आप्रवासन के मामले में, और न्यूज़ीलैंडवासियों के लिए बहुत कम प्राप्त करता है, जिसमें डेरी उत्पाद क्षेत्र भी शामिल है।

पीटर्स ने कहा, ''प्रति व्यक्ति आधार पर, राष्ट्रीय सरकार ने न्यूज़ीलैंड के श्रम बाजार में भारत को कहीं अधिक पहुंच दे दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने अपने को सुरक्षित करने के लिए नहीं दी थी। यह न्यूज़ीलैंड के वर्तमान श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अव्यावहारिक है, जहां बहुत से न्यूज़ीलैंडवासी बेरोजगारी या आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।''

उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीज़ा सृजित के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, खासतौर से भारत के नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीज़ा बनाने से न्यूज़ीलैंड में भारतीय आप्रवासन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जबकि हमारा श्रम बाजार पहले से ही बहुत तंग है।''

मोर का शिकार कर पार्टी करते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

उदयपुर, 22 दिसम्बर (कासं)। जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला गडावत गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक रूपलाल पुत्र प्रेमशंकर मीणा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है तथा दूसरा हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल पुत्र भगवान मीणा है, तीसरा आरोपी राकेश पुत्र कुरीचंद है। तीनों ही आरोपी एक गांव के हैं।

प्रकरण के अनुसार, रविवार को गश्त के दौरान एएसआई रमेशचन्द्र को ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला

- श्रृषभदेव थाना पुलिस ने ब्लॉक अध्यक्ष रुपलाल प्रेम शंकर मीणा के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल मीणा को भी पकड़ा।

गडावत गांव में नदी किनारे किसी जानवर का शिकार कर पार्टी करने के लिए पकाने की सूचना मिली। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जहां तीनों आरोपी शिकार किए गये राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाते मिले। तीनों को दबोचकर तथा इनके कब्जे से शिकार किए मोर के अवशेष जब्त कर, पूछताछ के लिए थाने लेकर आए।

वन विभाग अधिकारियों को सूचना देने पर वनरक्षक सुमित्रा ने मौके पर पहुंच आवश्यक कार्यवाही शुरू की। इधर इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)